

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 45/22

GCMS NO 2022/79

1. देवनारायण पुत्र नादान

2. भरोसी पुत्र नादान जाति गुर्जर निवासीयान सीतोड तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांत

बनाम

1. श्रीमती अनुष्का पत्नि गोविन्द सहाय पुत्री छीतर मल जाति मीना निवासी झाडोली तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर

2. दुलीराम पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी सीतोड तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर

3. भौरीलाल पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी सीतोड तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर

4. सरकार जरिये तहसीलदार वामनवास जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोंड

(अपील विरुद्ध निर्णय मु0नं0 41/20 दिनांक 29.6.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, वामनवास)  
अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा  
अभिभाषक रेस्पोंड श्री योगेश शर्मा

दिनांक 5.2.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध बंटवारा दिनांक 29.6.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, वामनवास पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांत/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इस आशय का पेश किया कि ग्राम सीतोड तहसील वामनवास में प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 75 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.04 है एवं ख0न0 76 रकबा 4.71 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। जिनमें जाने के लिए एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 77 के पश्चिम दिशा की ओर 20X60 फीट का रास्ता बना हुआ है। जो नजरी नक्शे में लाल रंग की लाईनो से दर्शित किया हुआ है। जिसमें होकर प्रार्थीगण अपने बुजुर्गों के समय से ही अपनी आराजीयात पर आते जाते रहे हैं तथा अपने कृषि यंत्रों व फसलों को लाते ले जाते रहे हैं। ख0न0 76 में फसल रखने के लिए चाह ख0न0 75 के पास ही तीन गैर दुपल्ला पाटोर का भी निर्माण किया हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 75 व 76 में आने जाने के लिए ख0न0 77 के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह रास्ता जयपुर रोड पर खुलता है। मौके पर ख0न0 77 में होकर मिटटी की रपट 20X60 फीट में बनी हुई है जिसमें होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि ख0न0 75 व 76 पर आते जाते रहे हैं एवं फसल लाते जाते रहे हैं। उसे रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से कई बार उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा टालम टोल करते हुए दिनांक 25.7.20 को स्पष्ट मना कर दिया गया। इस प्रकार आराजी ख0न0 77 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें लाल लाईन से दर्शित 20X60 फीट का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसके बाबत प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उचित प्रतिकर देने को तैयार है। इस प्रकार की इस अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।




अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। वहस उभयपक्ष अभिभाषकों की अपील

अपीलांट ने अपनी वहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प.51/2008 विविध क्रमांक 10547 दिनांक 5.10.20 जारी प्रपत्र का कोई अनुसरण नहीं किया गया। उक्त प्रपत्र अनुसार नियम 60 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मगवाई जाती है जिसमें नियमानुसार भू अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए इसके अभाव में मौका रिपोर्ट विधि के विपरीत होने के कारण अमान्य है तथा मौका रिपोर्ट में समस्त पक्षकारों को विधिवत सूचित कर देना चाहिए लेकिन इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर अपने कृषि कार्य हेतु स्वयं के पहुँचने अथवा कृषि यंत्रों को लाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे से होता है। नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है कि भूमि ख0न0 78 में से प्राप्त नहीं कर ख0न0 77 में से रास्ता चाहा है जबकि प्रार्थी की निकटतम रास्ता ख0न0 78 में बनता है। जो नहीं चाहा गया है। ऐसी स्थिति में चाहा गया अनुतोष विधि विरुद्ध होने से दिये जाने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने यदि मौके की वास्तविक रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर ली होती तो यह स्पष्ट हो जाता कि ख0न0 78 में आलरेडी प्लानिंग हो रही है तथा प्रार्थीगण अपीलांट सदैव से ख0न0 77 की मेड पर होकर अपने खेतों पर पहुँच रहे हैं तथा किस प्रकार किन दस्तावेजों के आधार पर यह माना है कि प्रार्थीगण अपीलांट को ख0न0 78 में होकर रास्ता लेना चाहिए था जबकि संबंधित रास्ता उक्त मेड पर होकर ही बनता है। इसके अलावा अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कहीं भी किसी भी किसी भी राजस्व रिकार्ड की कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.9.21 पर कोई मनन नहीं किया। क्योंकि किसी भी पक्षकार को अपने खेत पर रास्ता पहुँच मार्ग एक आवश्यक अधिकार है। जिसके लिए रास्ता होना या पहुँच मार्ग एक आवश्यक अधिकार है। इसी बाबत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 में संशोधन कर धारा 251 ए जोड़ी गई है। उक्त प्रावधान के अनुसार जहाँ रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माथेपुर

अभिलेख में दर्ज नहीं हो तथा कृषक द्वारा परम्परागत रूप से सुखाधिकार के रूप में जिस मार्ग का उपयोग किया जा रहा है उस बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित एवं कारण सहित आदेश पारित करना चाहिए लेकिन मातहत अदालत ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तो खारिज कर दिया लेकिन इस विषय पर अपना कोई मत पारित नहीं किया कि प्रार्थीगण अपने खेतों पर किस प्रकार कृषि कार्य हेतु पहुँच सकेंगे। निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब को अपने निष्कर्ष में दर्शाकर प्रार्थना पत्र इतिश्री कर ली है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई नजिरो में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि विचारण न्यायालय को अपने निर्णय में विस्तृत विवेचना राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र का आधार बनाकर निर्णय पारित करना चाहिए। इस प्रकार तहत न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधार पर विधि के विपरीत जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को गलत माना है। और कयास मात्र पर उक्त अपीलाधीन निर्णय खिलाफ जाकर पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब के अनुसार तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित कर दिया कि प्रार्थीगण को ख०न० 77 में से ना होकर ख०न० 78 में निकटतम रास्ता बनता है। निकटतम रास्ता किस प्रकार ख०न० 78 में से बनता है क्योंकि किसी की खातेदारी भूमि के मध्य में होकर किसी खातेदार को नुकसान पहुँचाया जाना उचित नहीं है। इस तथ्य पर कोई गौर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। क्योंकि अपने निर्णय में कोई विवेचना राजस्व रिकार्ड या मौके की नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी में न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायिक विवेक का कोई उपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर मौके पर प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता कायम किया जावे। जिससे की प्रार्थी की कृषि भूमि पर कृषि कार्य सुगमता से संचालित हो सके।

रेस्पोंडनेट ने अपील बहस में तर्क दिया कि अपीलाट द्वारा चाही गई भूमि में से कभी भी 20x60 फिट का कोई रास्ता नहीं रहा है ना ही वर्तमान में है। इसलिए अपीलाट का यह कथन झूठा है कि अपीलाट का उनके पूर्वजों के समय से ही उनकी आमद रफत का व फसल लाने ले जाते रहने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अपीलाट/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में गलत नक्शा पेश किया गया था। अपीलाट/प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार लाल डोटेड लाइन से जो रास्ता ख०न० 77 में होकर बताया है ऐसा कोई रास्ता ही नहीं। अपीलाट द्वारा काल्पनिक रूप से तथ्य अंकित किये गये हैं। हाल ख०न० 117 मुख्य सड़क हाईवे रोड है जिससे अपने खेत ख०न० 75 व 76 में प्रार्थीगण ख०न० 78 में होकर आते जाते रहे हैं तथा ख०न० 78 में होकर ही प्रार्थीगण/अपीलाट का निकटतम रास्ता है। अपीलाट/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोंडनेट की आराजीयात को हडपने की गरज से अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (1)(ए) में भी यह प्रावधान है कि यदि किसी भूमिधारी के पास अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है तो मुख्य रास्ते से उसकी भूमि तक जाने हेतु जा भी

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
महार्ज माधोप

निकटतम रास्ता जिस भी भूमि में से होकर निकलता हो, उसी भूमि में से रास्ता दिया जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी भूमि ख0न0 78 में होकर ही अपीलांट की खातेदारी पर जाने का रास्ता माना है। अपीलांट द्वारा गलत रूप से निकटतम रास्ता रेस्प0 की आराजीयात में से चाहा गया है जबकि अपीलांट की आराजी पर पहुँच का निकटतम रास्ता भूमि ख0न0 78 में से होकर जाता है। अपीलांट द्वारा रेस्प0 की भूमि को हडपने की गरज से भूमि ख0न0 77 में से रास्ता चाहा गया है भूमि ख0न0 78 में से रास्ता नहीं चाहा गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधि के अनुरूप ही खारिज किया है। जो विधि के अनुरूप है।  
अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा भूमि ख0न0 77 में से अपनी आराजीयात ख0न0 75 व 76 पर आने जाने हेतु रास्ता प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए तहत रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार कराई जाकर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता दिये जाने या नहीं दिये जाने बाबत निर्णय पारित करना होता है। इसके बाबत राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प.51/2008/विविध/10547 दिनांक 5.10.2020 के द्वारा निर्देशित किया गया है। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी रिपोर्ट के आराजी ख0न0 78 में निकटतम रास्ता होने एवं प्रार्थी/अपीलांट द्वारा भूमि ख0न0 78 में से रास्ता चाहे जाने का अनुतोष नहीं चाहने के आधार पर अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है तथा रास्ते के संबंध में कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक अधिकारी के स्तर से तैयार कराई जाकर, प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास निर्णय मु0न0 41/20 दिनांक 29.6.22 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भूमि ख0न0 75 व 76 पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है या नहीं, यदि नहीं है तो किस ख0न0 में निकटतम रास्ता उपलब्ध हो सकता है, के संबंध में कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर, प्राप्त रिपोर्ट एवं उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.3.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
नयाई माघोप